[श्री मोती भाई आर० चौधरी]

गया है कि अगर यह ट्रेनें 15 दिन में चालू नहीं करदी जायेंगी तो सत्याग्रह करने में आयेगा। अतः मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस विभाग में बहुत लम्बे समय से नीचे की जो दो ट्रेनें बन्द हैं, उनको जल्दी से चालू करवा दिया जाए, जिससे विद्यार्थियों, मजदूरों और कर्मचारियों को राहत हो। ये दो ट्रेनें नीचे के मुताबिक हैं :—

1. अहमदाबाद पाटण के बीच चलने वाली 120 डाउन गाड़ी।

2. 115–16 अप-डाउन गाड़ी जो अहमदाबाद पाटण के बीच वाया रगुज, चानसमा, बहुचराजी, कटोशन, कडी और कलोहल हो कर जाती है।

उपर्युक्त दो ट्रेनों को जल्दी से चालू करके हर रोज के यात्रियों को सुविधा दें और इस तरह से अपनी बढ़ती हुई रेल मूव में टकी प्रतीती करायें।

(viii) NEED TO RE-EMPLOY PUBLIC HEALTH VISITORS OF BIHAR WHOSE SERVICES WERE DISCONTINUED FROM 1ST SEPTEMBER, 1980.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2 अक्तूबर, 1977 से देश भर में चालू "जनस्वास्थ्य रक्षक" योजना को 1 सितम्बर, 1980 से बिहार में समाप्त कर दिया गया है।

पूर्वांचल राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कलकत्ते में बैठक लेकर एक प्रस्ताव पारित किया कि यह योजना जोरदार ढंग से चालू की जाए और अभी तक चलाया जा रहा है। यह योजना जनहित में बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है।

बिहार में 7 हजार जन-स्वास्थ्य रक्षकों की सेवाएं समाप्त होने से नियोजित युवकों में भारी आक्रोश पैदा हो रहा है। बिहार में बेरोजगारियां सब से अधिक हैं और सरकार राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम की घोषणा कर नियोजित युवकों को बेकारी ग्रस्त करने की अजीब स्थिति पैदा कर रही है। यह केवल बिहार में हुआ है जो सौतेला व्यवहार कहा जा सकता है।

अतः भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में समानता के आधार पर अन्य राज्यों में कार्यरत जन-स्वास्थ्य रक्षकों की तरह बिहार में भी सात हजार नवयुवकों को जन-स्वास्थ्य रक्षक की सेवा में पुनः नियोजित करे तथा उन्हें न्याय प्रदान करे।

(ix) NEED TO START THE PROPOSED KISAN SAHKARI CHINI MILL, LTD., MEHMOODABAD IN SITAPUR DISTRICT OF U.P.

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाना चाहता हूं।

26–3–74 को किसान सहकारी चीनी मिल लि० महमूदाबाद जिला सीमापुर, उत्तर-प्रदेश की निर्माण योजना स्वीकृत हुई। इस मिल के निर्माण हेतु कुल चौरासी एकड़ भूमि क्रय में 5.07 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। किसानों के विभिन्न समुदायों व संस्थाओं ने लगभग 22 लाख रुपया अंश पूंजी भी जमा किया है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 90 लाख रुपये का अंशदान दिया था।

जब से इस मिल के बनने की बातचीत चली है क्षेत्र की जनता किसान मजदूर आशा लगाये हैं। छः साल से अधिक समय बीत गया है लेकिन केवल उद्घाटन का पत्थर ही लग सका है।

मिल का निर्माण कार्य प्रारम्भ होना है। मशीनरी आदि का आर्डर दिया जाना है। सम्पत्ति कमेटी के मुताबिक योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई है। क्योंकि इस योजना के आधार पर सहकारी क्षेत्र में लगने वाली, अनेक चीनी मिलों को, सहायता व ऋण प्रदान किये जाते रहे हैं।

उक्त प्रोत्साहन योजना सन् 1975 में घोषित की गई थी। अगस्त, सन् 1978 से स्थगित कर दी गई। सरकार ने इस प्रोत्साहन योजना की समीक्षा और उसका पुनर्निरीक्षण करने के लिए फरवरी, सन्, 1980 को अन्तर मंत्रालय ग्रुप का गठन किया था। ज्ञात हुआ है कि इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है। केन्द्रीय सरकार मंत्री मंडल को इस योजना के बारे में निर्णय लेना हैं।

अहमदाबाद में किसन सहकारी चीनी मिल का बनना इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। पड़ौसी दो जनपदों जैसे लखनऊ, बाराबंकी के सीमावर्ती जिलों के किसान भी उन योजनाओं से लाभ उठा सकेंगे। सरकार इस मिल के निर्माण कार्य के प्रारम्भ किये जाने में प्रारंभ से ही उपेक्षा कर रही है। क्षेत्र के किसान मजदूर दुखी हैं। कृषि पर आधारित इस उद्योग के लगने से इस पिछड़े क्षेत्र में सर्वसाधारण के चहुंमुखी विकास के द्वार खुलेंगे।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि अविलम्ब मंत्रिमंडल द्वारा जो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की जाये और भारत के औद्योगिक वित्त निगम अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से इस मिल के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता अविलम्ब प्रदान कराई जावे।

(x) MEASURES TO CURB LATE RUNNING OF TRAINS AND EXTENSION OF SERVICES OF CERTAIN TRAINS LIKE GAUHATI MAIL, DUDHUWA MAIL, ETC.

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय सदन में उठाना चाहती हूं।

मेरे लोक सभा के क्षेत्र में रेलवे का बहुत ही कम फैलाव है। हालांकि यह क्षेत्र फसल आदि में काफी अच्छा है, आवागमन एवं मालवाहन के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। जो भी रेलवे के साधन हैं वे न तो पर्याप्त ही हैं और न रेलें समय से चलती हैं। गौहाटी मेल करीब करीब रोजाना ही 6–8 घण्टे देर से चलती है। यह सेवा अभी तक भी बरेली तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस बारे में मैंने पहले भी रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया था। ऐसा लगता है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जनता बहुत परेशान है। मेरी यह भी दरख्वास्त है कि दुधुवा मेल, जो स्वर्गीय बाल गोविन्द वर्मा जी के प्रयासों से चलाई गई थी, दुधुवा तक न जाकर मिलानी तक ही जाती है। यह सेवा शीघ्र ही दुधुवा तक उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा एक रेल सेवा जो फरुखाबाद से शाहजहांपुर को चलती है वो मोहम्मदी होती हुई गोला गोरखनाथ लखीमपुर खीरी क्षेत्र को भी उपलब्ध होनी चाहिए।

क्योंकि मैं बार-बार इस बारे में रेल मंत्रालय का ध्यान दिला चुका हूं और अभी तक इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं हुई है, ये विषय मुझे सदन में उठाने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे कि इस पर तुरन्त कार्यवाही हो सके।